चुनाव याचिका

न्यायमूर्ति डी.के महाजन के समक्ष

भगवान दास सिंगला,-याचिकाकर्ता.

बनाम

हरचंद सिंह और अन्य,-प्रतिवादी।

Election Petition No. 1 of 1969

8 सितम्बर 1969.

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम(1951 का XLIII)—धारा 36—भारत का संविधान (1950)—अनुच्छेद 173—मतदाता सूची में आने वाले व्यक्ति का नाम—निर्णायक धारणा कि वह 21 वर्ष का है—चाहे उत्पन्न हो—ऐसी धारणा—क्या निर्णायक रूप से योग्यता साबित होती है अनुच्छेद 178 के तहत आयु - नामांकन पत्र की जांच की तारीख पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जांच - का दायरा - नामांकन पत्र स्वीकार करने वाले रिटर्निंग अधिकारी का आदेश - चाहे अंतिम हो।

अभिनिर्धारित किया गया कि जिस क्षण किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दिखाई देता है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1952 की धारा 36(7) के तहत एक निर्णायक धारणा उत्पन्न होती है, कि वह एक मतदाता है और आवश्यक रूप से इक्कीस वर्ष से अधिक आयु का है। यह अनुमान केवल यह दर्शाता है कि संबंधित व्यक्ति ने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लेकिन यह हर मामले में निर्णायक रूप से यह नहीं दिखाएगा कि उम्मीदवार की आयु संविधान के अनुच्छेद 173 द्वारा निर्धारित परीक्षणों को पूरा करती है। दूसरे शब्दों में धारा 36(7) के तहत 25 वर्ष की आयु पूरी करना अनुमान से बाहर है। ऐसे अभ्यर्थी का नामांकन पत्र संवैधानिक योग्यता के अभाव में प्रथम दृष्टया खारिज किया जाना आवश्यक हैसबूत है कि उसके पास उम्र के संबंध में योग्यता नहीं है। (पैरा 11 और 12)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि जांच की तारीख पर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जाने वाली जांच का दायरा यह है कि उसे एक उम्मीदवार के नामांकन कागज़ पत्र को स्वीकार करना होगा जब तक कि मतदाता सूची में या नामांकन के चेहरे पर योग्यता की कमी स्पष्ट न हो। यदि योग्यता के अभाव में इस दोष को उसके द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है या कोई आपत्ति उठाई जाती है और उस आपत्ति पर की गई जांच में, रिटर्निंग ऑफिसर उसके सामने रखी गई सामग्रियों पर गलत निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो नामांकन पत्र की स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। एक उचित स्वीकृति होना हालाँकि, ऐसी स्वीकृति अंतिम नहीं है और चुनाव याचिका दायर होने पर चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा जांच के लिए खुली है। ट्रिब्यूनल इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि उम्मीदवार बिल्कुल भी योग्य नहीं है और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उसके नामांकन पत्र की स्वीकृति उचित नहीं थी। इसी प्रकार नामांकन पत्रों की अनुचित अस्वीकृति के मामले में, न्यायाधिकरण अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर आ सकता है। (पैरा 13)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80 और 81*धाराओं के तहत याचिका* में प्रार्थना की गई है कि श्री हरचंद सिंह-प्रतिवादी का चुनाव *लेहरा गागा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव में लौटे उम्मीदवार को रद्द कर दिया जाए और चुनाव को शून्य घोषित कर दिया जाए।*

सिंच बैंस, वकील,याचिकाकर्ता के लिए.

जोगिंदर सिंह रेखी, एडवोकेट,प्रतिवादी संख्या 1 के लिए।

जे.एन.कौशल, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ क्लोरीन लाकियानपाल अनोहै-विमल, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 के लिए।

निर्णय

न्यायमूर्ति महाजन,- एकमात्र आधार, जिस पर निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग की गई है, वह यह है कि याचिकाकर्ता का नामांकन पत्र अनुचित तरीके से खारिज कर दिया गया था।

(2) याचिकाकर्ता एक वकील है. जब मध्यावधि चुनाव का आदेश दिया गया तब पंजाब राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन था। इस याचिका में विवाद लहरागागा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। इस निर्वाचन क्षेत्र को 1 जनवरी, 1969 को विधान सभा में अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए बुलाया गया था। नामांकन पत्र 4 जनवरी, 1969 से 8 जनवरी, 1969 तक दाखिल किए जाने थे। 7 जनवरी को , 1969, याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और उन्हें बताया गया कि नामांकन पत्रों की जांच 9 जनवरी 1969 को की जाएगी, जो उस उद्देश्य के लिए निर्धारित तिथि थी। जिस समय नामांकन पत्रों की जांच की गई, उस समय याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं हुए। उनके नामांकन पत्र पर किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। रिटर्निंग ऑफिसर ने स्वत: संज्ञान लेते हुए उनके नामांकन पत्र को खारिज कर दिया और अपना निर्णय इस प्रकार दर्ज किया-

"वर्तमान:-कोई नहीं।"

आयु संबंधी योग्यता स्पष्ट रूप से पूरी न होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया।

(एसडी.) . . .

9-1-69

सुबह 11.30 बजे

रिटर्निंग ऑफिसर।"

इसके बाद, मतदान 9 फरवरी, 1969 को हुआ। मतपत्रों की गिनती 11 फरवरी, 1969 को हुई और उसके बाद कार्य); और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम संख्या 43) (इसके बाद इसे 1951 अधिनियम कहा जाएगा)। 1950 अधिनियम की धारा 14 प्रत्येक मतदाता सूची की तैयारी या संशोधन के संबंध में 'अर्हता तिथि' को 1 जनवरी के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें इसे तैयार या संशोधित किया जाता है। धारा 16 मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अयोग्यताओं की गणना करती है। यह सामान्य मामला है कि याचिकाकर्ता को इस धारा के तहत कोई अयोग्यता नहीं मिली है। धारा 19 पंजीकरण की शर्तें प्रदान करती है और इन शर्तों में है: -

"19. पंजीकरण की शर्तें:-इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक व्यक्ति जो-

(a) अर्हता तिथि पर इक्कीस वर्ष से कम आयु न हो; और

(b) किसी निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी है, उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

इसलिए, इक्कीस वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति निर्वाचक के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकता है। धारा 21 और 22 में मतदाता सूची की तैयारी और पुनरीक्षण और मतदाता सूची में प्रविष्टियों के सुधार का प्रावधान है।

(10) जहां तक 1951 अधिनियम का संबंध है, इस याचिका के प्रयोजनों के लिए जिन प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वे धारा 2(ई) और 36 हैं। धारा 2(ई) एक 'निर्वाचक' को परिभाषित करती है और निम्नलिखित शर्तों में है: -

"2. व्याख्या:- (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(a) ****
(b) ****
(c) ****
(d) ****

(e) किसी निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में 'निर्वाचक' का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसका नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की उस समय लागू मतदाता सूची में दर्ज है और जो इसमें उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन नहीं है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 16।

(एफ)
(जी)
(एच)
(मैं)
(2) *
(3) * * $
(4) * *
(15) * * *

धारा 36 निम्नलिखित शर्तों में है:

"36. नामांकन की जांच.- (1) धारा 30 के तहत नामांकन की जांच के लिए निर्धारित तिथि पर, उम्मीदवार, उनके चुनाव एजेंट, प्रत्येक उम्मीदवार का एक प्रस्तावक, और प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा विधिवत लिखित रूप से अधिकृत एक अन्य व्यक्ति, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति नहीं , ऐसे समय और स्थान पर उपस्थित हो सकता है जो रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करे; और रिटर्निंग अधिकारी उन्हें सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच करने के लिए सभी उचित सुविधाएं देगा जो समय के भीतर और धारा 33 में निर्धारित तरीके से वितरित किए गए हैं।

(2) रिटर्निंग अधिकारी तब नामांकन पत्रों की जांच करेगा और किसी भी नामांकन पर की गई सभी आपत्तियों पर निर्णय लेगा और या तो ऐसी आपत्ति पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, ऐसी संक्षिप्त जांच के बाद, यदि कोई हो, जैसा कि वह आवश्यक समझे, किसी भी नामांकन को अस्वीकार कर सकता है। निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर:-

(a) कि नामांकन की जांच के लिए निर्धारित तिथि पर उम्मीदवार या तो योग्य नहीं है या निम्नलिखित प्रावधानों में से किसी के तहत सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए अयोग्य है, जो लागू हो सकता है, अर्थात्: -

अनुच्छेद 84, 102, 173 और 191,

(इस अधिनियम का भाग II, और केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 4 और 14),

(b) कि धारा 33 या धारा 34 के किसी भी प्रावधान का अनुपालन करने में विफलता हुई है; या

(c) कि नामांकन पत्र पर अभ्यर्थी (अथवा प्रस्तावक) के हस्ताक्षर असली नहीं हैं।

(3) उपधारा (2) के खंड (बी) या खंड (सी) में निहित किसी भी बात को नामांकन पत्र के संबंध में किसी भी अनियमितता के आधार पर किसी भी उम्मीदवार के नामांकन को अस्वीकार करने के लिए अधिकृत नहीं माना जाएगा, यदि ऐसा किया जा सकता है।" तारीख किसी अन्य नामांकन पत्र के माध्यम से विधिवत नामांकित किया गया है जिसके संबंध में कोई अनियमितता नहीं की गई है।

(4) रिटर्निंग अधिकारी किसी भी नामांकन पत्र को किसी भी दोष के आधार पर अस्वीकार नहीं करेगा जो पर्याप्त चरित्र का नहीं है।

(5) रिटर्निंग अधिकारी धारा 30 के खंड (बी) के तहत इस संबंध में नियुक्त तिथि पर जांच करेगा और कार्यवाही के किसी भी स्थगन की अनुमति नहीं देगा, सिवाय इसके कि जब ऐसी कार्यवाही दंगे या खुली हिंसा या उसके नियंत्रण से परे कारणों से बाधित या बाधित हो। .

बशर्ते कि यदि कोई आपत्ति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उठाई जाती है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाती है, तो संबंधित उम्मीदवार को अगले दिन से पहले नहीं बल्कि जांच के लिए निर्धारित तिथि के बाद का समय दिया जा सकता है, और रिटर्निंग अधिकारी को जिस तारीख को कार्यवाही स्थगित की गई है उस पर अपना निर्णय दर्ज करें।

(6) रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक नामांकन पत्र पर उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने के अपने निर्णय का समर्थन करेगा और, यदि नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाता है, तो ऐसी अस्वीकृति के अपने कारणों का एक संक्षिप्त विवरण लिखित रूप में दर्ज करेगा।

(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी निर्वाचन क्षेत्र की वर्तमान मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति इस तथ्य का निर्णायक साक्ष्य होगी कि उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक है, जब तक कि वह यह साबित हो गया है कि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 16 में उल्लिखित अयोग्यता के अधीन है।

(8)) सभी नामांकन पत्रों की जांच और उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने के तुरंत बाद निर्णय लिया जाएगा दर्ज किए गए हैं, रिटर्निंग अधिकारी वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा, यानी ऐसे उम्मीदवार जिनके नामांकन वैध पाए

गए हैं, और इसे अपने नोटिस बोर्ड पर चिपकाएंगे।

एकमात्र अन्य प्रावधान, जिसका संदर्भ आवश्यक रूप से दिया जाना है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 173 है; और इसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

(9) 3. कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधानमंडल में सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह-

(a) भारत का नागरिक है, और चुनाव आयोग द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर हस्ताक्षर करता है;

(b) विधान सभा में सीट के मामले में, आयु पच्चीस वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और विधान परिषद में सीट के मामले में, आयु तीस वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए; और

(c) ऐसी अन्य योग्यताएं रखता है जो संसद द्वारा या उसके द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत निर्धारित की जा सकती हैं।

(11) इन प्रावधानों के संयुक्त पढ़ने से यह स्पष्ट है कि एक बार जब किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जाता है, तो एक निर्णायक धारणा होती है कि वह एक निर्वाचक है जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता कि वह 1950 की धारा 16 में उल्लिखित अयोग्यता के अधीन है। अधिनियम की धारा 16 में उम्र के संबंध में कोई अयोग्यता नहीं है। निर्वाचक के रूप में शामिल होने के लिए आयु केवल योग्यता का मामला है। इससे स्पष्ट हो सकता है कि यदि किसी को मतदाता सूची में मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराना है तो उसकी उम्र इक्कीस वर्ष से कम होना एक तरह से अयोग्यता है। लेकिन 1950 अधिनियम की धारा 16 के तहत, यह उसमें उल्लिखित अयोग्यताओं में से एक नहीं है। निर्वाचक का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज किया गया है और केवल उसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जा सकता है जिसकी आयु इक्कीस वर्ष है और, किसी भी मामले में, यह स्पष्ट धारणा है कि वह व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, उसकी उम्र इक्कीस वर्ष है। पीडब्लू-1, रिटर्निंग ऑफिसर, कुलदीप सिंह के साक्ष्य में यह आया है कि: -

"*

*निर्वाचक नामावली, प्रदर्शनी पीडब्लू-1/2 वर्ष 1965 के लिए तैयार की गई थी। मेरे पास संशोधित मतदाता सूची की प्रति थी।

हर साल मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है। मतदाता सूची, प्रदर्शनी पीडब्लू-1/2, अंततः 24 दिसंबर, 1968 को प्रकाशित की गई। मतदाता सूची निस्संदेह 1965 में मुद्रित की गई थी, लेकिन इसे 24 दिसंबर, 1968 को प्रमाणित किया गया था, और तिथि तक हुए कोई भी बदलाव प्रमाणीकरण को मतदाता सूची में लाल स्याही से दर्शाया गया है। आपत्तियां दर्ज होने और निर्णय के बाद मतदाता सूची में अतिरिक्त नाम भी हैं। संपूर्ण मतदाता सूची मुद्रित नहीं है। मध्यावधि चुनाव में, मतदाता सूची का पुनर्मुद्रण नहीं किया जाता है; इसमें केवल संशोधन किया गया है। मतदाता सूची का मूल भाग 15, प्रदर्शनी पीडब्लू-1/2, 1965 में मुद्रित किया गया था लेकिन संशोधित भाग 1968 में किसी समय मुद्रित किया गया था। याचिकाकर्ता का नाम मतदाता सूची के मूल भाग में है। 1965 में छपी मतदाता सूची 1 जनवरी, 1965 की स्थिति को दर्शाएगी।

उनकी गवाही से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का नाम वर्ष 1965 में तैयार की गई मतदाता सूची में

मौजूद था, जो मतदाता सूची 1 जनवरी, 1965 से प्रभावी है। इसलिए, एक स्पष्ट निर्णायक धारणा उत्पन्न हुई कि 1 जनवरी, 1965 को , याचिकाकर्ता की उम्र इक्कीस वर्ष से कम नहीं थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र को खारिज करते समय 1951 अधिनियम की धारा 36(7) के प्रावधानों की अनदेखी की और इस प्रकार नामांकन पत्र को खारिज करना अनुचित था। इस मामले पर मैंने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसे सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य की विभिन्न घोषणाओं से और अधिक समर्थन मिलता है। बृजेंद्रलाल गुप्ता और अन्य बनाम ज्वालाप्रसाद और अन्य (1) में, धारा 36 (7) के प्रावधानों पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य ने पाया कि: -

> "* * इस प्रकार जब धारा 36(7) के तहत कोई अनुमान लगाया जाता है तो इसका मतलब प्रथम दृष्टया हो सकता हैकि संबंधित व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से कम न हो। *****
>
> यह स्पष्ट है कि धारा 36(7) के तहत उठाया गया अनुमान नामांकन पत्र की वैधता के बारे में दलील को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि उक्त अनुमान केवल यह दर्शाता है कि संबंधित व्यक्ति के पास 121 वर्ष की आयु पूरी कर ली. ****"

दुर्गा शंकर मेहता बनाम ठाकुर रघुराज सिंह और अन्य (2) में, *न्यायमूर्ति* मुखर्जी, (जैसा कि वह तब थे) ने धारा 36(7) के प्रावधानों पर ध्यान देने के बाद कहा:-

> "* * दूसरे शब्दों में, मतदाता सूची निर्वाचक की योग्यता के संबंध में निर्णायक है, सिवाय इसके कि जहां अयोग्यता स्पष्ट रूप से आरोपित या साबित हो। **"

अयोग्यता के प्रयोजनों के लिए, किसी को 1950 अधिनियम की धारा 16 का संदर्भ लेना होगा। जैसा कि पहले ही कहा गया है, अनुच्छेद 173 के तहत योग्यता की कमी 1950 अधिनियम की धारा 16 के तहत अयोग्यता नहीं है।

बृजेंद्रलाल गुप्ता और अन्य बनाम ज्वालाप्रसाद और अन्य (1) में, *न्यायमूर्ति* गजेंद्रगडकर, (जैसा कि वह तब थे), 1951 अधिनियम की धारा 36(7) से निपटते समय, रिपोर्ट के पृष्ठ 378 पर, इस प्रकार देखा गया: -

> "** इस संबंध में, धारा पर विचार करना प्रासंगिक है
>
> अधिनियम की धारा 36(7) के तहत जो अनुमान लगाया गया है और उसका प्रभाव। जैसा कि हमने पहले ही देखा है, धारा 36(7) के तहत मतदाता सूची में प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति इस तथ्य का निर्णायक सबूत होगी कि उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक है; लेकिन यह याद रखना चाहिए कि यह अनुमान इस धारा के प्रयोजनों के लिए उठाया गया है और इसे स्पष्ट रूप से इस उपधारा के अंतिम खंड के अधीन बनाया गया है, यानी, अनुमान तब तक उत्पन्न हो सकता है जब तक यह साबित न हो जाए कि प्रश्न में व्यक्ति 1950 के अधिनियम की धारा 16 में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन है। विशेषण 'निर्णायक' का उपयोग जो 'सबूत' को योग्य बनाता है तकनीकी रूप से अनुचित है क्योंकि प्रमाणित प्रति के उत्पादन से उत्पन्न होने वाली धारणा किसी भी तरह से निर्णायक नहीं है।
>
> यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रासंगिक साक्ष्य के निर्णायक चरित्र के संबंध में भौतिक प्रावधान जैसा कि यह मूल रूप से था, बाद में 1956 के अधिनियम 27 द्वारा संशोधित किया गया है। मूल रूप से, प्रावधान यह था कि संबंधित प्रविष्टि सही J का निर्णायक साक्ष्य होगी। उस प्रविष्टि में नामित कोई भी निर्वाचक चुनाव में खड़ा हो सकता है, या जैसा भी मामला हो, नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर कर सकता है। विधायिका ने स्पष्ट रूप से सोचा कि इन शब्दों द्वारा अधिकृत अनुमान अनावश्यक रूप से व्यापक था, और

इसलिए, संशोधन द्वारा, प्रथम दृष्टया और खंडन योग्य अनुमान अब व्यक्ति की क्षमता तक सीमित है। एक निर्वाचक के रूप में माने जाने के संबंध में और कुछ नहीं, और वह भी तब तक जब तक कि यह साबित न हो जाए कि वह धारा 16 में उल्लिखित किसी अयोग्यता से ग्रस्त है। धारा 16 जिसका संदर्भ इस प्रकार दिया गया है, तीन शीर्षकों के तहत मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अयोग्यता निर्धारित करती है। - (ए) कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, (बी) कि वह विकृत दिमाग का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, या (सी) किसी भी कानून के प्रावधानों के तहत मतदान से कुछ समय के लिए अयोग्य है। चुनाव के संबंध में भ्रष्ट और अवैध प्रथाओं और अन्य अपराधों से संबंधित। इस प्रकार, स्थिति यह है कि प्रासंगिक प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति प्रथम दृष्टया दिखाएगी कि संबंधित व्यक्ति उक्त किसी भी अयोग्यता के अधीन नहीं है, लेकिन इस प्रथम दृष्टया धारणा को इसके विपरीत साक्ष्य द्वारा खंडित किया जा सकता है।

इस मामले का एक और पहलू है जिसका संदर्भ दिया जा सकता है। धारा 36(7) के तहत जो खंडन योग्य अनुमान उत्पन्न होता है, वह केवल एक निर्वाचक के रूप में संबंधित व्यक्ति की स्थिति को संदर्भित करता है। आइए विचार करें कि इस धारणा का क्या अर्थ है। किसी निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में अधिनियम की धारा 2. उप-धारा 1(ई) के तहत एक निर्वाचक का अर्थ है 'एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उस समय के लिए दर्ज है और जो विषय नहीं है। 1950 के अधिनियम की धारा 16 में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के लिए।'

यह हमें मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए 1950 के अधिनियम की धारा 19 द्वारा निर्धारित शर्तों पर ले जाता है। धारा 19 में प्रावधान है कि उक्त अधिनियम के भाग III के पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन प्रत्येक व्यक्ति, जो अर्हता तिथि (ए) पर 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है, और (बी) सामान्य रूप से एक निर्वाचन क्षेत्र में रहता है, हकदार होगा उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत होना। इस प्रकार जब धारा 36(7) के तहत कोई अनुमान लगाया जाता है तो इसका प्रथम दृष्टया अर्थ यह हो सकता है कि संबंधित व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से कम नहीं है और वह सामान्य तौर पर उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी है; लेकिन नामांकन पत्र की वैधता के लिए यह साबित करना होगा कि उम्मीदवार ने 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। संविधान का अनुच्छेद 173 जो राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है, यह प्रावधान करता है कि कोई व्यक्ति उस संबंध में तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह (ए) भारत का नागरिक न हो, (बी)

विधान सभा में सीट के मामले में, कम से कम 25 वर्ष की आयु, और (सी) ऐसी अन्य योग्यताएं रखता है जो संसद द्वारा या उसके द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत निर्धारित की जा सकती हैं। खुद को उम्र के बारे में आवश्यकता तक ही सीमित रखते हुए, यह स्पष्ट है कि धारा 36(7) के तहत उठाया गया अनुमान नामांकन पत्र की वैधता के बारे में दलील को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि उक्त अनुमान केवल यह दर्शाता है कि संबंधित व्यक्ति के पास 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली, यह स्पष्ट है कि 21 या 25 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के संबंध में, उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाएंगे और इसलिए वे अन्यथा योग्य होने पर मतदाता होंगे और फिर भी वे राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव में खड़े होने के हकदार नहीं होंगे। इस प्रकार, यह मान लेना सही नहीं होगा कि मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति का संदर्भ हर मामले में निर्णायक रूप से दिखाएगा कि उम्मीदवार की आयु संविधान के अनुच्छेद 173 द्वारा निर्धारित परीक्षण को पूरा करती है; दूसरे शब्दों में, 25 वर्ष की आयु पूरी करने की आवश्यकता धारा 36(7) के तहत अनुमान से बाहर है, और

यही कारण है कि निर्धारित नामांकन फॉर्म के लिए आवश्यक है कि उम्मीदवार को उक्त फॉर्म पर हस्ताक्षर करते समय इस बारे में एक घोषणा करनी होगी उनकी उम्र। यह विचार हमारे निष्कर्ष का समर्थन करता है कि उम्र के बारे में घोषणा महत्व का विषय है और उक्त आवश्यकता का अनुपालन करने में विफलता को एक अप्रमाणिक चरित्र का दोष नहीं माना जा सकता है।* * *"

(12) इस प्रकार उपरोक्त प्राधिकारियों से यह प्रतीत होता है कि जैसे ही किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में आता है, एक निर्णायक धारणा उत्पन्न होती है कि वह एक निर्वाचक है और आवश्यक रूप से इक्कीस वर्ष से अधिक आयु का है। अत: मतदाता सूची में यह प्रविष्टि कि मतदाता की आयु बीस वर्ष है, वास्तव में निरर्थक है। वास्तव में, ऐसी प्रविष्टि का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। इस संबंध में रूप लाल मेहता बनाम धन सिंह और अन्य (3) में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले को देखें, जिसमें इसे इस प्रकार रखा गया था: -

* मतदाता सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, किसी व्यक्ति का वोट, जिसका नाम मतदाता सूची में है, को इस आधार पर शून्य होने के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि योग्यता तिथि पर उसकी आयु 21 वर्ष से कम थी।

(3) आई.एल.आर (1968)1 पंजाब और हरियाणा 651 (एफबी)-1967 पी.एल.आर 618

बृजेंद्रलाल गुप्ता के मामले (1) में, हालांकि निर्वाचक की उम्र 48 वर्ष बताई गई थी, लेकिन उस प्रविष्टि को उनकी उम्र के बारे में निर्णायक नहीं माना गया और नामांकन पत्र में उम्र घोषित करने की चूक को "घातक माना गया।" धारा 36(7) के तहत अनुमान की निर्णायक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, किसी व्यक्ति को उस दिन 21 वर्ष की आयु माना जाना चाहिए जिस दिन उसका नाम मतदाता सूची में उल्लेखित है, अर्थात उस दिन। निर्वाचक माना जाता है या निर्वाचक है/नामांकित है। मौजूदा मामले में, वह तारीख 1 जनवरी, 1965 है; और इस पर कोई विवाद नहीं है. इसलिए, जिस दिन नामांकन पत्र दाखिल किया गया, शुद्ध अंकगणितीय गणना के अनुसार, याचिकाकर्ता की आयु 25 वर्ष से अधिक थी और इसलिए, उसका नामांकन पत्र खारिज नहीं किया जा सकता था।

(13) यह दिखाने के लिए आगे बढ़ने से पहले कि वर्तमान रिकॉर्ड पर यह बिना किसी संदेह के साबित हो गया है कि, वास्तव में, प्रासंगिक समय पर याचिकाकर्ता की उम्र 25 वर्ष से अधिक थी, विद्वान वकील के तर्क का निपटारा करना उचित होगा। प्रतिवादी नंबर 1 के लिए, अर्थात्, नामांकन पत्र को खारिज करने वाले रिटर्निंग अधिकारी का आदेश निर्णायक है और एक चुनाव याचिका में एक न्यायाधिकरण, उस आदेश के पीछे नहीं जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया जा सकता कि याचिकाकर्ता की उम्र प्रासंगिक समय में 25 वर्ष से अधिक थी। जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है, नामांकन पत्र, प्रथम दृष्टया, बिल्कुल सही क्रम में था। उम्र की घोषणा से पता चला कि याचिकाकर्ता की उम्र 25 वर्ष से अधिक थी। नामांकन पत्र पूर्ण था और अन्य सभी मामलों में कानून के अनुरूप था। इसे महज मतदाता सूची के संदर्भ में खारिज कर दिया गया। मतदाता सूची में याची की उम्र 20 वर्ष दर्ज थी। यह भी महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 1, श्री हरचंद सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है, कि:-

"** मैंने कहा कि उसके कागजात खारिज नहीं किए जाने चाहिए और वह चुनाव लड़ने की अनुमति मिलनी चाहिए. ***"।

सवाल यह उठता है कि जांच की तारीख पर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जाने वाली जांच का दायरा क्या है। यह मामला रेस इंटीग्रा का नहीं है. दुर्गा शंकर मेहता के मामले (2) में, *न्यायमूर्ति* मुखर्जी, (जैसा कि वह तब थे) ने कहा:—■

> "* * * * JJ एक अनुचित स्वीकृति होती, यदि योग्यता की कमी चुनावी पर स्पष्ट होती

> स्वयं या नामांकन पत्र के मुख पर रोल करें और रिटर्निंग ऑफिसर ने उस दोष को नजरअंदाज कर दिया या यदि कोई आपत्ति उठाई गई और उम्मीदवार में योग्यता की अनुपस्थिति के बारे में जांच की गई और रिटर्निंग ऑफिसर पहले रखी गई सामग्रियों पर गलत निष्कर्ष पर पहुंचे। उसे। जब इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन की स्वीकृति को उचित माना जाना चाहिए यह निश्चित रूप से अंतिम स्वीकृति नहीं है और चुनाव न्यायाधिकरण, उसके समक्ष रखे गए साक्ष्यों पर, इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि उम्मीदवार बिल्कुल भी योग्य नहीं था। लेकिन चुनाव को उम्मीदवार की संवैधानिक अयोग्यता के आधार पर शून्य माना जाना चाहिए, न कि इस आधार पर कि उसका नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया था। **

इन टिप्पणियों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि रिटर्निंग ऑफिसर को नामांकन पत्र स्वीकार करना पड़ता था जब तक कि मतदाता सूची में या नामांकन पत्र के चेहरे पर योग्यता की कमी स्पष्ट न हो और उस दोष को उसके द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था या आपत्ति उठाई गई थी और जांच में उस आपत्ति पर, रिटर्निंग ऑफिसर उसके सामने रखी गई सामग्रियों पर गलत निष्कर्ष पर पहुंचे थे। लेकिन यदि इनमें से कुछ भी नहीं होता है, तो स्वीकृति को उचित स्वीकृति माना जाएगा। विद्वान न्यायाधीश ने यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसी स्वीकृति भी अंतिम नहीं होगी और न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि उम्मीदवार बिल्कुल भी योग्य नहीं था। लेकिन उम्मीदवार का चुनाव संवैधानिक अयोग्यता के आधार पर रद्द होगा, न कि नामांकन पत्र की अनुचित स्वीकृति के आधार पर। मेरी राय में, ये टिप्पणियाँ अनुचित अस्वीकृति के मामले में भी समान रूप से लागू होंगी। वर्तमान मामले में, अस्वीकृति संवैधानिक योग्यता की कमी के आधार पर थी और यह मानने के लिए कि योग्यता की इतनी कमी थी, रिटर्निंग ऑफिसर ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मतदाता सूची का सहारा लिया था। लेकिन उन्होंने धारा 36(7) के प्रावधानों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टि के बावजूद, JJ याचिकाकर्ता की आयु 20 वर्ष थी, रिटर्निंग ऑफिसर को इस आधार पर आगे बढ़ना था कि 1 जनवरी, 1965 को याचिकाकर्ता की आयु 21 वर्ष से कम नहीं थी। यदि कानून की इस स्थिति को ध्यान में रखा गया होता, तो रिटर्निंग ऑफिसर ने वह गलती नहीं की होती, जिसमें वह फंस गया। दुर्गा शंकर मेहता का केस निपटाते समय

(2), एसएम बनर्जी बनाम श्रीकृष्ण अग्रवाल (4) में, *न्यायमूर्ति* सुब्बा राव, ने इस प्रकार कहा: -

> * >जे<उनका निर्णय, इस प्रस्ताव के लिए एक स्पष्ट अधिकार है कि यदि योग्यता की कमी नामांकन पत्र के चेहरे पर दिखाई नहीं देती है और यदि रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उस आधार पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है, तो इसकी स्वीकृति नामांकन को उचित स्वीकृति माना जाना चाहिए। * * ""

हालाँकि, केटी वेलुस्वामी थेवर बनाम जी राजा नैनार और अन्य (5) में *न्यायमूर्ति* वेंकटराम अय्यर, की स्पष्ट घोषणा के मद्देनजर, प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील का तर्क, कि अस्वीकृति का आदेश रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पारित नामांकन पत्र अंतिम है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये अवलोकन इस प्रकार हैं:-

> "** प्रतिवादी की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्रो
>
> ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही वास्तव में रिटर्निंग अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील के माध्यम से होती है, और इसलिए, चुनाव याचिका में जांच का दायरा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष जांच के साथ सह-विस्तारित होना चाहिए, और इसे तक ही सीमित होना चाहिए। उसके सामने जमीन ली गई। यह तर्क दिया गया था कि किसी निर्णय को केवल उस आधार के संदर्भ में अनुचित कहा जा सकता है जिसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एक विशेष तरीके से सामने रखा और तय किया गया था, और इसलिए, 'अनुचित तरीके से खारिज' की अभिव्यक्ति, इसके वास्तविक अर्थ में होगी , ट्रिब्यूनल के समक्ष जांच के दायरे को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उठाए गए आधार तक सीमित रखें।
>
> हम इस तर्क से सहमत नहीं हो पा रहे हैं, ट्रिब्यूनल चुनाव याचिका की सुनवाई में जिस क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, भले ही वह धारा 100(एल)(सी) के तहत कोई प्रश्न उठाता हो, वह रिटर्निंग अधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील की प्रकृति में नहीं है। चुनाव याचिका अधिनियम की धारा 81 के तहत एक याचिका की प्रस्तुति द्वारा शुरू की गई एक मूल कार्यवाही है। उत्तरदाताओं को उत्तर के रूप में लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार है; मुद्दों को तैयार करना होगा, और अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान याचिका के परीक्षण को नियंत्रित करते हैं। सभी पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार है, और वह है

(4) 22ई.एल.आर 64
(5) ए.आई.आर 1959 एस.सी 422।

> अपील के माध्यम से 1 कार्यवाही की तुलना में मूल कार्यवाही का सार। कार्यवाही का चरित्र होने के नाते, लागू नियम वह है जो सभी मूल कार्यवाहियों के परीक्षण को नियंत्रित करता है; यानी, किसी पार्टी के लिए यह खुला है कि वह दावे के समर्थन या उसे नकारने के लिए सभी आधार सामने रखे, केवल ऐसी सीमाओं के अधीन जो अधिनियम में पाई जा सकती हैं। ****",

(14) एस.एम बनर्जी के मामले (4) में, एक विवाद उठाया गया था कि दुर्गा शंकर मेहता के मामले (2) और वेलुस्वामी थेयर (5) के मामले में निर्णयों के बीच विरोधाभास था; और *न्यायमूर्ति* सुब्बा राव, (जैसा कि वह तब थे), एस.एम बनर्जी के मामले (4) में, वेलुस्वामी थेयर के मामले (5) में*न्यायमूर्ति* वेंकटरामा, की टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित किया, अर्थात्: -

> "यह उस मुद्दे पर सीधी घोषणा नहीं है जो अब विवाद में है और इसे स्वीकार कर लिया गया है।"

इसके बाद विद्वान न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं: -

> "* *आरपीजेएलई के दो निर्णय एक साथ खड़े हो सकते हैं और वे दो अलग-अलग स्थितियों से निपटते हैं: पहले में, नामांकन पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी, जबकि बाद में, अयोग्यता के आधार पर आपत्ति उठाई गई थी; लेकिन चुनाव याचिका में, अयोग्यता के अतिरिक्त आधारों का आरोप लगाया गया था और साबित करने की मांग की गई थी: एक अनुचित स्वीकृति के मामले से संबंधित है और दूसरा अनुचित अस्वीकृति के मामले से संबंधित है। हालाँकि बाद के निर्णय में

कुछ टिप्पणियाँ पहले के निर्णय के विपरीत निष्कर्ष पर आने के लिए आगे बढ़ाई गई थीं, *न्यायमूर्ति* वेंकटराम अय्यर, जो दोनों निर्णयों में पक्षकार थे, ने पहले वाले को इस आधार पर अलग कर दिया कि यह नहीं था बाद में उठाए गए सवाल पर सीधी घोषणा, पहले वाला फैसला पांच जजों का था लेकिन बाद वाला तीन जजों का था। विद्वान न्यायाधीशों ने, जिन्होंने बाद के मामले का फैसला किया, अपने फैसले और पहले वाले फैसले के बीच कोई विरोधाभास नहीं देखा। यद्यपि श्री ए.वी. विश्वनाथ शास्त्री द्वारा दिए गए तर्क में कुछ ताकत है, और, यदि यह समग्र होता, तो हममें से कुछ लोग इसके पक्ष में हो सकते हैं

> पहले के फैसले के तर्क और निष्कर्ष से सहमत नहीं होने के कारण, यह अदालत अपने पहले के फैसले से बंधी हुई है और हमें इस प्रश्न को बड़ी पीठ के पास भेजने का कोई औचित्य नहीं दिखता, खासकर जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उच्च न्यायालय भौतिक संशोधन को अस्वीकार करते हुए ट्रिब्यूनल द्वारा अपने विवेक से पारित आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था। * *"।

(15) इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तविक कानूनी स्थिति यह है कि अर्हता तिथि पर मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का प्रवेश इस तथ्य का निर्णायक प्रमाण है कि उसकी आयु 21 वर्ष से अधिक है। लेकिन अभ्यर्थी के पास संवैधानिक योग्यता यह होनी चाहिए कि उसकी आयु 25 वर्ष हो। ऐसे उम्मीदवार का नामांकन पत्र संवैधानिक योग्यता के अभाव में खारिज कर दिया जाए, इसके लिए प्रथम दृष्टया सबूत होना चाहिए कि उसके पास उम्र के संबंध में योग्यता नहीं है; और भले ही इस मामले पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कोई निर्णय दिया गया हो, वह निर्णय अंतिम नहीं है और चुनाव याचिका दायर होने पर चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा इसकी जांच की जा सकती है।

(16) वर्तमान मामले में, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिसके आधार पर वह यह कह सके कि याचिकाकर्ता की उम्र 25 वर्ष से कम थी। याचिकाकर्ता की घोषित उम्र पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। मतदाता सूची में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के आधार पर ही नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया, मैं 'गलत' इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मामले में पेश किए गए सबूत ऐसा साबित करते हैं। किसी भी स्थिति में, रिटर्निंग ऑफिसर को धारा 36(7) के तहत इस धारणा के आधार पर आगे बढ़ना था कि अर्हता तिथि पर उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से अधिक थी। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र की अस्वीकृति अनुचित थी और उस आधार पर, निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव शून्य घोषित किया जाना चाहिए।

(17) एकमात्र अन्य प्रश्न, जिसकी जांच की जानी बाकी है, वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता यह साबित करने में सक्षम है कि वह वास्तव में, उस तारीख को 25 वर्ष का था जब उसने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। 1 याचिकाकर्ता ने इस संबंध में साक्ष्य पेश किया है; और अब मैं प्रदर्श PW-2/2 का उल्लेख करूंगा, सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पीएनमेगा के प्रवेश और निकासी रजिस्टर से प्रविष्टि है 'आईएस प्रविष्टि' याचिकाकर्ता की जन्म तिथि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार संगत तिथि है 17 जून 1942 को आता है, प्रदर्शनी PW-4/1

मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की प्रति है और उसमें याचिकाकर्ता की उम्र 17 जून, 1942 दर्ज है। परिणाम राजपत्र, प्रदर्शनी R2W-1/2 के उद्धरण में, याचिकाकर्ता की जन्म तिथि वही है। प्रदर्श PW-4/2 याचिकाकर्ता द्वारा पुलिस उप-निरीक्षक के पद के लिए लोक सेवा आयोग को किया गया एक आवेदन है; और उसमें भी, उनकी जन्मतिथि 17 जून, 1942 दर्ज की गई है। PW-3,

पियारे लाल, कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका समिति, लेहरागागा से गवाह के रूप में पूछताछ की गई। उनसे जन्म रजिस्टर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था और उन्होंने कहा कि नगरपालिका समिति के पास जन्म रजिस्टर संबत 2001 से शुरू हुए थे। इसलिए, वर्ष 1999 बीके के लिए जन्म रजिस्टर उपलब्ध नहीं।

याचिकाकर्ता एक वकील है और उसने 1965 में एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसने 1959 में मैट्रिक किया। वह 9वीं कक्षा में फेल हो गया। सबूतों की इस स्थिति के आधार पर, कोई भी वैध रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 17 जून, 1942 है।

(18) स्कूल रजिस्टर में किसी व्यक्ति की उम्र की प्रविष्टि के साक्ष्यात्मक मूल्य के संबंध में बहुत सारे तर्क दिए गए। लेकिन दोनों पक्षों के विद्वान वकील इस बात पर सहमत थे कि ये प्रविष्टियाँ साक्ष्य के प्रासंगिक टुकड़े हैं और इसके विपरीत मामूली साक्ष्य उन्हें विस्थापित कर सकते हैं। वर्तमान मामले में, ऐसा कोई सबूत नहीं है जो स्कूल रजिस्टर के साथ-साथ मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में प्रविष्टियों पर संदेह पैदा करे। वास्तव में, याचिकाकर्ता की जन्मतिथि का उल्लेख प्रदर्शनी आर2 डब्ल्यूएल/2 में भी मिलता है। रिकॉर्ड की इस स्थिति में, यह मानना अनुचित नहीं होगा कि याचिकाकर्ता का जन्म 17 जून, 1942 को हुआ था। ये प्रविष्टियाँ वर्तमान विवाद उत्पन्न होने से बहुत पहले से मौजूद थीं। प्रतिवादी, श्री हरचंद सिंह के विद्वान वकील द्वारा यह समझाने की बहुत कोशिश की गई कि याचिकाकर्ता के पिता और माँ गवाह-बॉक्स में उपस्थित नहीं हुए हैं। मेरी राय में, उनके गैर-उत्पादन से मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे बस इतना ही कह सकते थे कि याचिकाकर्ता का जन्म अमुक तारीख को हुआ था और इससे अधिक कुछ नहीं। उनकी केवल मौखिक गवाही होगी। और, किसी भी स्थिति में, एकमात्र स्रोत, जहां से दस्तावेजों में उल्लिखित तारीख प्राप्त की जा सकती थी, वी माता-पिता होंगे। उनका गैर-उत्पादन गंभीर हो सकता था यदि प्रतिवादी द्वारा इसके विपरीत मामूली सबूत भी दिया गया होता। इस स्थिति में, यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख में 25 वर्ष से अधिक उम्र का था।

(19) अत: यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का नामांकन पत्र इस आधार पर खारिज किया गया कि वह योग्यता से कम था

टिपर चंद वि.मातु राम, आदि (सोढ़ी, जे.)'

उम्र अनुचित थी. मैं तदनुसार याचिकाकर्ता के लिए एकमात्र मुद्दा पाता हूं।

(20) इसलिए, परिणाम यह हुआ कि इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया और निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव शून्य घोषित कर दिया गया। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ममता,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
रोहतक, हरियाणा।